आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 24.07.2024
समय 1830

मुख्य समाचार :–

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा – सरकार, राज्य की शिक्षा व्यवस्था को व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रयासरत।
- सर्वोच्च न्यायालय, लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत आयोजित करेगा।
- डेंगू की रोकथाम के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने दून एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र में कंट्रोल रूम स्थापित किया।

संसद

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप को खारिज किया है। आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष लगातार यह धारणा बनाने का प्रयास कर रहा है कि विपक्षी दलों वाले राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी बजट में हर राज्य का नाम नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी विशेष राज्य का उल्लेख बजट भाषण में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि केंन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन राज्यों को नहीं मिलेगा।
आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि केन्द्रीय बजट सरकार को बचाने का प्रयास था। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसका विरोध करेगा। श्री खरगे ने यह भी कहा कि विकास कैसे होगा जब बजट ही संतुलित नहीं है। बाद में विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया।

बजट प्रतिक्रिया

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आम बजट को विकसित भारत के लक्ष्य को साधने, नये अवसरों को सृजित करने और प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में उत्तराखंड को पिछले वर्ष आपदाओं से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए विशेष सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई है। इसके अर्न्तगत बजट में 86 करोड़ की प्रारंभिक धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस बार केंद्रीय बजट से प्रदेश को 2 हजार 217 करोड रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। सतपाल महाराज ने बताया कि बजट में प्रदेश में 4 सौ 75 गांव और बसावटों तक सड़क पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उत्तराखंड उद्योग संघ के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किये गये वित्तीय वर्ष 2024–25 के आम बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं को रोजगार से जोड़ने का ध्यान रखा गया है।
नैनीताल के किसान आनंदमणि भट्ट ने केंद्रीय बजट 2024–25 के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और अपने विचार साझा किए।

लोकार्पण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार, राज्य की शिक्षा व्यवस्था को व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने के लिए योजना बनाई जा रही है। वे देहरादून में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के नए भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री धामी ने कहा कि यह भवन प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों में भी सुधार लाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी सुविधाओं का मजबूत करने का प्रयास कर रही है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

बच्चों की नैतिक और पर्यावरण शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि यदि हम बच्चों को पर्यावरण और नैतिक मूल्य संबंधित शिक्षा दी जाए, तभी वे भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता पुरस्कार भी वितरित किए।

निर्देश

कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि कांवड़ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने हरिद्वार मेला क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम के लिये विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।

इस बीच, कांवड़ मेले के दौरान नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए गठित पुलिस टीम ने दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार पुलिस ने इनके पास से 25 किलोग्राम गांजा बरामद किया है।

विशेष लोक अदालत

सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। यह पहल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष में एक मील का पत्थर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उन नागरिकों से इस पहल से लाभ उठाने की अपील की है जिनके मामले शीर्ष अदालत में लंबित हैं।

कंट्रोल रूम

डेंगू की रोकथाम के लिए देहरादून जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने दून एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र– डी.आई.सी.सी.सी में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यहां इलाज, बेड, जांच और प्लेटलेट्स से संबंधित जानकारी एक कॉल पर मिलेगी। कंट्रोल रूम में नगर निगम के कार्मिक और स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सकों की तैनाती की गई है।

डेंगू से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या और शिकायत तथा चिकित्सकीय परामर्श के लिए टोल फ्री नंबर 1 8 0 0 1 8 0 2 5 2 5 पर संपर्क किया जा सकता है। जिलाधिकारी सोनिका ने जनता से मानसून के दौरान डेंगू की संभावना के मद्देनज़र आम जनता से सतर्क रहने के साथ ही अपने आसपास सफाई रखने और पानी जमा न होने देने का अनुरोध किया।

समीक्षा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। श्री धामी ने तीर्थ पुरोहितों के साथ विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की और इस संबंध में सुझाव मांगे। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर उत्तराखंड के सतत विकास और प्रदेश की खुशहाली व कल्याण की कामना की।

पासपोर्ट ऑफिस

गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भेंट की। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री से गोपेश्वर और कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण स्थानीय छात्रों व नौजवानों को पासपोर्ट कार्यालय के खुलने से सुविधा होगी और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले युवाओं का समय और धन भी बचेगा। विदेश मंत्री ने श्री बलूनी के प्रस्ताव पर सकारात्मक सहमति जताई है।

अनुबंध

भारतीय मानक ब्यूरो–बी.आई.एस और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीच मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है। इसका उद्देश्य बी.आई.एस के सहयोग से विश्वविद्यालय में मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म का विकास करना है। इसका उपयोग भारतीय मानकों के अनुसार विभिन्न कृषि प्रथाओं और नई तकनीकों के परीक्षण और प्रयोग के लिए किया जाएगा। इन फार्मों में कृषि इनपुट, उपकरण, जल प्रबंधन, कीट प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन भारतीय मानकों के अनुसार होंगे।

ये फार्म विभिन्न हितधारकों को कृषि प्रथाओं और नई तकनीकों पर प्रशिक्षण देने, प्रदर्शित करने या जागरूकता पैदा करने के लिए उपयोग किए जाएंगे। ये फार्म कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों को अपनाने, कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने और कृषि उत्पादों की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेंगे।

ट्रायल

चमोली जिले में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के ट्रायल कल और 27 जुलाई को खेल मैदान गोपेश्वर में लिए जाएंगे। प्रभारी जिला क्रीडाधिकारी जयबीर रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत जिले के आठ से 14 आयु वर्ग के डेढ़ सौ बालक व डेढ सौ बालिकाओं का चयन किया जाएगा। चयनित छात्र हर महीने पन्द्रह सौ रुपए की छात्रवृति के पात्र होंगे।

प्रतिभाग के इच्छुक, गूगल प्ले स्टोर से UKSRS SPORTS एप डाउनलोड कर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। आयु की गणना एक जुलाई 2024 को आधार मानकर की जाएगी और प्रतिभागी के उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।